जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

चूरू

Rashtradoot

फोनः- 256906, 256907, फैक्सः- 01562-256908 वर्षः 17 संख्याः 17 प्रभात चूरू, गुरुवार 15 मई, 2025 पो. रजि. न. चूरू/084/2019-21 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

'बलूचिस्तान ने अपने आप को पाकिस्तान से अलग देश घोषित किया

बलूच प्रतिनिधि मीर यार बलोच ने एक्स पर यह घोषणा करते हुए विश्व से अपील की कि अब ''शांत'' रहने का समय नहीं है

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 14 मई। बलूच प्रतिनिधि मीर यार बलोच ने बलुचिस्तान को पाकिस्तान से स्वतंत्र घोषित कर दिया है, उन्होंने इस घोषणा का कारण क्षेत्र में दशकों से जारी भारी हिंसा, जबरदस्ती लोगों को उठा ले जाने और मानवाधिकार हनन को बताया।

उन्होंने कहा, ''तुम मारोगे, हम निकलेंगे। हम नस्ल बचाने निकले हैं। आओ, हमारा साथ दो। पाकिस्तान अधिकृत बलूचिस्तान के बलोच लोग सड़कों पर हैं और यह उनका राष्ट्रीय फैसला है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान नहीं है और अब दुनिया सिर्फ मूक दर्शक नहीं बनी रह सकती।''

भारतीय नागरिकों, खासकर मीडिया, यूट्यूबर्स और बुद्धिजीवियों से उन्होंने अनुरोध किया कि वे बलूचों को ''पाकिस्तान के अपने लोग'' कहना बंद करें।

उन्होंने कहा, ''बलूच नैरेटिव!! प्रिय भारतीय राष्ट्रवादी मीडिया, यू ट्यूब साथी और भारत के बचाव में लगे बुद्धिजीवियों से अनुरोध है कि बलूचों को ''पाकिस्तान के अपने लोग'' न कहें। हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम बलूचिस्तानी हैं। पाकिस्तान के असली अपने लोग पंजाबी हैं, जिन्हें कभी भी हवाई बमबारी, जबरन गायब किए जाने या नरसंहार का सामना नहीं करना पड़ा।''

- हालांकि, पाकिस्तान से अलग देश होने के बलूच निवासियों के इस प्रयास को पूर्ण सफलता मिलना कोई आसान काम नहीं है, पर, मीर यार बलोच की विश्व से अपील काफी मार्मिक है।
- स्वतंत्र होने की इस घोषणा के साथ, एक डॉक्यूमैंट्री फिल्म भी रिलीज़ की, जो ''बलूचिस्तान'' के निवासियों के मुंह ज़ुबानी बयानों पर आधारित है।
- डॉक्यूमैंट्री के अनुसार, दशकों से, ''बलूचिस्तान'' विश्व की दृष्टि से ओझल सा रहा है। हालांकि, ''बलूचिस्तान'' में प्राकृतिक संपदा तथा बेशकीमती खनिजों का भंडार है, पर, फिर भी यह क्षेत्र सदा पाकिस्तान के शासकों के रडार पर नहीं आ पाया। अब तक इस अवहेलना के कारण, स्वायत्तता व पहचान के लिये संघर्ष करता रहा है।

मीर यार बलोच ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) पर भारत के रुख का पूरा समर्थन भी किया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान पर उस क्षेत्र को खाली करने का दबाव बनाने की अपील की।

इसी बीच, एक नई डॉक्यूमेंट्री ''बलूचिस्तान: द लॉन्ग रोड टू रैज़िस्टैंस'' भी ध्यान आकर्षित कर रही है। यह फिल्म बलूच नागरिकों के वास्तविक अनुभवों को गहराई से दिखाती है, जिनकी आवाजें लंबे समय से दमन के कारण खामोश थीं।

बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे उपेक्षित प्रांत है, दशकों से अंतर्राष्ट्रीय ध्यान से वंचित रहा है। प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध होने के बावजूद, यह क्षेत्र गरीबी से त्रस्त है और लंबे समय से स्वतंत्रता और पहचान की लड़ाई लड़ रहा है।

जबरन गायब कर देना, हिरासत में यातना, ग़ैर-न्यायिक हत्याएं और मीडिया पर सेंसरशिप- बलूच लोगों ने इन सबका सामना किया है। इनमें से कई घटनाएं तो सामने भी नहीं आई हैं। पीड़ितों, गुमशुदा लोगों के परिवारों और कार्यकर्ताओं की गवाही इस संगठित दमन की डरावनी सच्चाई को उजागर करती है।

यह फिल्म भारत की ओर से ''ऑपरेशन सिंदूर'' (पहलगाम नरसंहार के जवाब में की गई कार्रवाई) के बाद रिलीज़ हुई है। यह याद दिलाती है कि जब दुनिया की सुर्खियाँ सीमा पार आतंक पर केन्द्रित होती हैं, तब पाकिस्तान की अपनी सीमाओं के भीतर एक मौन युद्ध जारी रहता है।

बलूच नेता की इस घोषणा ने पाकिस्तान के सामने एक नया रणनीतिक संकट खड़ा कर दिया है, जो पहले से ही कई मोर्चों पर जूझ रहा है। आज की यह घोषणा भारत को एक राजनयिक हथियार देती है, जिससे पाकिस्तान को बैकफुट पर लाया जा सकता है।

हालांकि बलूच लोगों के लिए पाकिस्तान से स्वतंत्रता प्राप्त करना आसान नहीं होगा, फिर भी यह घटनाक्रम

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नाबालिग को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्तों को आजीवन कारावास

जयपुर, 14 मई। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 महानगर द्वितीय ने नाबालिग को होटल में बंधक बनाकर कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त मोनू उर्फ मोईन खान और श्रवण सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही पीठासीन अधिकारी राजवीर सिंह ने दोनों अभियुक्तों पर कुल 1.04 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अरुण कुमार जाटावत और पीड़ित पक्ष की ओर से अधिवक्ता कुणाल शर्मा ने बताया कि घटना को लेकर पीड़िता ने 15 अगस्त,

- पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने 15 अगस्त 2023 को दर्ज मामले में फैसला सुनाया।

2023 को जालूपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी अपने पिता से किसी बात पर अनबन हो गई थी। यह बात उसकी बहन को पता चलने पर वह उसे जयपुर ले आई और होटल में दो दिन साथ रहे। इस दौरान, उसकी बहन ने मोनू से, अपना धर्म का भाई बताकर, मिलाया। इसके बाद उसकी बहन उसे वहां यह कहकर छोड़ गई कि मोनू उसका ध्यान रखेगा। रिपोर्ट में कहा गया कि बहन के जाते ही मोनू ने उसके साथ दुष्कर्म किया और बंधक बना लिया। अभियुक्त मोनू रोज रात को आता और उसके साथ दुष्कर्म करता।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बुधवार को कांग्रेस ने सीडब्ल्युसी की बैठक आयोजित की

बैठक में एक प्रस्ताव पारित कर प्र.मंत्री मोदी से पूछा कि वे इतने चुप और शांत क्यों हैं?

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 14 मई। क्या भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नरेन्द्र मोदी की स्थिति अयुक्तियुक्त (अनटैनेबल) हो रही है?

यह प्रश्न संघ परिवार के अंदर विभिन्न स्तरों पर पूछा जा रहा है, लेकिन इससे भी ज्यादा रोचक तथ्य यह है कि यह सवाल दिल्ली में स्थित विदेश राजनयिकों के बीच भी सुनाई दे रहा है, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद के परिप्रेक्ष्य में आमतौर से मोदी जी के भविष्य के बारे में चिंतन करते रहते हैं।

आरएसएस यह प्रश्न कर रही है कि आखिर मोदी अपने अपमान पर चुप क्यों हैं, जबकि राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने मोदी के खिलाफ बयान दिये हैं तथा डंके की चोट पर यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि नरेन्द्र मोदी अमेरिका के दबाव के आगे झुक गये और युद्धविराम के लिये सहमत हो गये, जबकि सैन्य स्थिति भारत के लिये बहुत अच्छी थी तथा देश युद्ध में विजय के नज़दीक था।

कांग्रेस ने आज शाम कांग्रेस वर्किंग कमेटी (सीडबल्यूसी) की एक और मीटिंग बुलाई तथा उसमें एक प्रस्ताव पारित कर मोदी से पूछा है कि वे खामोश क्यों हैं तथा कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस ने पूछा है कि पहलगाम के आतंकियों का क्या हुआ, वे कहाँ हैं? कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री को एक सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिये तथा सबको जानकारी देनी चाहिये। ज्ञातव्य है कि प्रधानमंत्री मोदी पिछली दो मीटिंगों में उपस्थित नहीं हुये हैं। कांग्रेस यह भी कह रही है कि सरकार, भारत और पाकिस्तान को बराबर के स्तर पर रखे जाने पर आपत्ति नहीं जता रही है। कांग्रेस ने यह जानना चाहा है कि क्या यह स्थिति (दोनों देशों को बराबर के स्तर पर रखा जाना) मोदी जी को स्वीकार्य है?

- सर्वदलीय बैठक बुलाकर विपक्ष से ''शेयर'' क्यों नहीं करते, पहलगाम की घटना का विवरण और उसके बाद का घटनाक्रम।
- जैसा कि विदित ही है, 25 मई को प्र.मंत्री मोदी ने एनडीए के मु.मंत्रियों की एक बैठक बुलाई है। अतः सीडब्ल्युसी की बैठक के प्रस्ताव के जरिए विपक्ष यह सवाल उठा रहा है कि एनडीए के मु.मंत्रियों की बैठक के लिये तो प्र.मंत्री के पास समय है, पर, सर्वदलीय बैठक के लिये क्यों नहीं?
- कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने सीडब्ल्युसी की बैठक के बाद टिप्पणी की कि नड्डा जीवनपर्यंत भाजपा अध्यक्ष नहीं रह सकते, अतः उनके स्थान पर नया अध्यक्ष बनने के बाद, प्र.मंत्री मोदी का क्या होगा?

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

उदयपुर के मार्बल व्यापारियों ने तुर्की से व्यापारिक संबंध समाप्त किये

व्यापारियों में गहरा आक्रोश है कि तुर्की आतंकवाद का समर्थन करने वाले पाकिस्तान का साथ दे रहा है

उदयपुर, 14 मई (कासं)। भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच तुर्किये द्वारा पाकिस्तान का समर्थन करने पर उदयपुर के मार्बल व्यापारियों ने राष्ट्र हित में तुर्किये के साथ सभी व्यापारिक संबंध समाप्त करने की घोषणा की है।

उदयपुर मार्बल एसोसिएशन के अध्यक्ष पंकज गंगावत ने बताया कि हालांकि तुर्किये के साथ उनके पुराने और अच्छे व्यापारिक संबंध रहे हैं और बड़ी मात्रा में ग्रेनाइट मार्बल का आयात किया जाता रहा है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में यह व्यापार जारी नहीं रखा जा सकता। व्यापारियों का स्पष्ट कहना है कि 'दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन होता है' और उनके लिए व्यापारिक हितों से पहले देश का हित महत्वपूर्ण है। व्यापारी समुदाय में इस बात को लेकर गहरा आक्रोश है कि तुर्किये भारत के खिलाफ आतंकवाद को समर्थन देने वाले पाकिस्तान का साथ दे रहा है। गंगावत ने बताया कि तुर्किये से हमारे व्यापारिक रिश्ते अच्छे रहे हैं, जिस कारण काफी मार्बल व्यापारी तुर्किये से ग्रेनाइट मार्बल का आयात करते हैं। तुर्की इसको नजरअंदाज करते हुए हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान को सहयोग कर रहा है। इससे हमारे मार्बल व्यापारियों में बहुत ही आक्रोश है।

- मार्बल एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि तुर्की से हर साल बड़ी तादाद में ग्रेनाइट व मार्बल का आयात किया जाता है। उन्होंने कहा, उनके लिये व्यापारिक हित से पहले देश हित है।

गंगावत बताते है कि तुर्किये से हर साल बड़ी तादाद में ग्रेनाइट मार्बल आयात किया जाता है, जो कि वर्तमान स्थिति में राष्ट्रीयता के खिलाफ है। गंगावत ने तो सरकार से कहा कि तुर्किये के साथ मार्बल व्यापार को पूरे देश में प्रतिबंधित करें। व्यापारिक प्रतिबंध के साथ ही पर्यटन को भी बंद किया जाए। उन्होंने बताया कि मेवाड़ में उदयपुर मार्बल व्यवसाय का बडा हब हैं और यहां तुर्किये से हजारों टन मार्बल आयात किया जाता है, ऐसे में उदयपुर मार्बल प्रोसेसर समिति के सदस्यों ने बड़ा निर्णय लेते हुए तुर्किये से मार्बल आयात करने का बहिष्कार शुरू किया है।

उदयपुर मार्बल प्रोसेसर समिति के अध्यक्ष कपिल सुराणा कहते है कि हमने तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर तुर्किये से सभी व्यापारिक रिश्ते तोड़ने की मांग की हैं। वे बताते है कि फिलहाल पूरे देश में जितना मार्बल आयात किया जाता है, उसका 70 प्रतिशत हिस्सा सिर्फ तुर्किये से आयात

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बिना विभागीय जाँच के कर्मचारी को बर्खास्त नहीं कर सकते

जयपुर, 14 मई। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि बिना विभागीय जांच के, केवल एफआईआर के आधार पर कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता कांस्टेबल को बिना जांच ही सेवा से बर्खास्त करने

- हाई कोर्ट ने केवल एफआईआर के आधार पर सेवा से बर्खास्त करने को अवैध करार दिया तथा सभी सेवा परिलाभ के साथ बहाल करने का आदेश दिया।

वाले पुलिस विभाग के आदेश को मनमाना व अवैध करार देते हुए उसे सभी सेवा परिलाभ सहित सेवा में बहाल करने का आदेश दिया है। अदालत ने अपीलेट अथॉरिटी के आदेश को भी रद्द करते हुए कहा कि वह अपील में उठाए गए मुद्दों पर विचार करने में फेल रहा है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

चीन-बाँग्लादेश धुरी उभर रही है नॉर्थ-ईस्ट में

चीन ने अरुणाचल के कई स्थानों को नया नाम देना शुरु किया तथा इस क्षेत्र को ''दक्षिण तिब्बत'' बताया

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 14 मई। युद्धविराम - विवाद, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच शांतिदूत बनने के अमेरिकन राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के दावे ने नया विवाद खड़ा कर दिया है, के बीच, चीन और बाँग्लादेश भारत के पूर्व के सीमावर्ती राज्यों में परेशानी खड़ी करते प्रतीत हो रहे हैं।

बताया जाता है कि चीन ने अरुणाचल के बहुत से स्थानों के नये नाम रख दिये हैं। भारत ने चीन की इस गतिविधि को ''निरर्थक एवं हास्यास्पद'' करार दिया है, जिससे सम्बंधित क्षेत्र के भारत का अभिन्न हिस्सा होने की स्थिति (स्टेटस) बदलने वाली नहीं है।

चीन ने दावा किया कि अरुणाचल ''दक्षिणी तिब्बत'' है। उसने हाल ही में भारतीय राज्य अरुणाचल के विभिन्न स्थानों के नामों की एक सूची जारी की है। इसकी प्रतिक्रिया में, भारत के विदेश मंत्रालय ने आज एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि ''इन स्थानों को नये नाम देने से यह अकाट्य वास्तविकता, जो संदेह से परे है, नहीं बदलेगी कि अरुणाचल भारत का अभिन्न एवं अहस्तान्तरणीय हिस्सा था, है और सदैव रहेगा।

- दूसरी ओर बाँग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद युनूस ने भी बाँग्लादेश, नेपाल, भूटान तथा नॉर्थ ईस्ट के सात राज्यों के लिये ''इकोनॉमिक प्लान'' का प्रस्ताव रखा है।
- पिछले दिनों, युनूस ने चीन यात्रा के दौरान टिप्पणी की थी कि नॉर्थ ईस्ट, ''लैण्ड लॉक्ड'' है तथा समुद्र तक पहुँचने का इस राज्य के पास कोई रास्ता नहीं है। अतः इस क्षेत्र के लोगों को आपस में मिलकर, माल बनाना चाहिये जो चीन को बेचा जायेगा।

दूसरी ओर, मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अन्तरिम बाँग्लादेश सरकार ने एक बार फिर बेसुरा राग अलापते हुये, एक व्यापक आर्थिक एकीकरण योजना प्रस्तावित की है, जिसमें बाँग्लादेश, नेपाल, भूटान तथा भारत के सात उत्तर -पूर्वी राज्य सम्मिलित किये गये हैं। गौरतलब बात यह है कि यूनुस ने इसमें भारत का जिक्र न करते हुये, केवल पूर्वोत्तर राज्यों का ही उल्लेख किया है। कुछ दिन पहले, अपनी चीन यात्रा के दौरान, यूनुस ने बाँग्लादेश को उत्पादन, लॉजिस्टिक्स तथा व्यापार के क्षेत्र में चीन के प्रमुख क्षेत्रीय पार्टनर के रुप में प्रस्तुत कर दिया था, तथा भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों को ''लैन्डलॉक्ड'' (जमीन से घिरे हुये) करार दिया था। बाँग्लादेश में चीन को अत्यधिक निवेश के लिये आमंत्रित करते हुये, यूनुस ने अपने देश को ''महासागर का एकमात्र अभिभावक'' बताया था। इस पृष्ठभूमि में देखने पर, यूनुस का ताजा प्रस्ताव भारत के लिहाज से टकराव का संकेतक लगता है।

नोबल पुरस्कार प्राप्त मोहम्मद यूनुस ने ये टिप्पणियाँ नेपाल के ''हाउस ऑफ रिप्रजेन्टेटिव्स'' के डिप्टी स्पीकर के साथ हुई अपनी मीटिंग में कीं, जो इस समय बाँग्लादेश की यात्रा पर आये हुये हैं। यूनुस ने हाइड्रोपावर, हैल्थकेयर तथा ट्रांसपोर्टेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में सीमा-पार के सहयोग (क्रॉस बॉर्डर कॉलेबरेशन) को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि इस सैक्टर से सम्बंधित सामान संयुक्त रुप से बाँग्लादेश में निर्मित किया जाये तथा चीन को बेच दिया जाये।

अर्थशास्त्री तथा प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य, संजीव सान्याल ने यूनुस द्वारा चीन से की गई इस आर्थिक अपील में भारत के

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पाकिस्तान रेंजर्स ने बीएसएफ जवान को छोड़ा

नयी दिल्ली, 14 मई। पाकिस्तान रेंजर्स ने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवान पूर्णम कुमार शॉ को छोड़ दिया है।

शॉ 20 दिन से पाकिस्तान रेंजर्स के कब्जे में थे। बीएसएफ ने बुधवार को प्रेस विज्ञिप्त जारी कर कहा, आज सुबह 10.30 बजे कांस्टेबल पूर्णम कुमार शॉ को अटारी-वाघा सीमा पर बीएसएफ

- सीमा सुरक्षा बल का जवान पूर्णम कुमार शॉ गत 23 अप्रैल को गलती से पाकिस्तान सीमा में चला गया था।

द्वारा पाकिस्तान से वापस लाया गया। विज्ञिप्त के अनुसार, शॉ 23 अप्रैल 2025 को लगभग 11.50 बजे फिरोजपुर सेक्टर में ऑपरेशनल ड्यूटी पर रहते हुए अनजाने में पाकिस्तान की सीमा में चले गए थे और उन्हें पाक रेंजर्स ने हिरासत में ले लिया था। विज्ञिप्त में कहा गया है कि पाकिस्तान रेंजर्स के

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अनिता आनन्द के कैनडा का विदेश मंत्री बनने से बहुत आशाएं जगी हैं

खासतौर पर भारत और कैनडा के तनावग्रस्त रिश्तों में सुधार की संभावनाएं देखी जा रही हैं

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 14 मई। कैनडा की नई विदेश मंत्री के रूप में अनिता आनंद की नियुक्ति देश की विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ का संकेत देती है - विशेष रूप से भारत के साथ बेहद तनावपूर्ण संबंधों की पृष्ठभूमि में। आनंद, जो कि दूसरी पीढ़ी की भारतीय मूल की कैनडा नागरिक हैं, ने भगवद् गीता पर हाथ रखकर पद की शपथ ली। यह प्रतीकात्मक इशारा एक शक्तिशाली संदेश देता है: कैनडा की यह शीर्ष राजनयिक कैनडा और भारत, दोनों पहचानों से गहराई से जुड़ी हुई हैं।

यह दोहरी विरासत उऐसे समय में एक राजनयिक सेतु के रूप में कार्य कर सकती है, जब दोनों देशों को इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है।

सन् 2023 में कैनडा-भारत संबंध उस समय सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए थे, जब ट्रूडो सरकार ने भारतीय एजेंसियों पर, कैनडा के सिख अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में कथित संलिप्तता के गंभीर आरोप लगाए। इसके परिणाम तुरंत सामने आए: राजनयिक निष्कासन, व्यापार वार्ताओं का ठप्प होना और वीज़ा सेवाओं पर रोक। कई महीनों तक संवाद बंद रहा और गतिरोध बना रहा।

अनिता आनंद का विदेश मंत्री बनना ऐसे समय में हुआ है जब दोनों देशों को राजनयिक संबंधों में सुधार से लाभ मिल सकता है। आनंद की भारतीय विरासत केवल प्रतीकात्मक नहीं है, यह पहचान उन्हें भारत की वैश्विक स्थिति के पीछे की सांस्कृतिक और राजनीतिक संवेदनाओं की स्वाभाविक समझ देती है। साथ ही, इस पहचान के कारण, प्रवासी समुदाय में उग्रवाद जैसे मुद्दों पर शांति से बातचीत करने के लिए उन्हें एक अनूठी मिली है। यह मुद्दा द्विपक्षीय संबंधों में एक बड़ा अवरोध रहा है।

- अनिता आनन्द ने गीता पर हाथ रखकर अपने पद की शपथ ली और अपने भारतीय मूल पुरजोर तरीके से प्रस्तुत किया
- पर, कैनडा-भारत रिश्ते, जो पिछली ट्रूडो सरकार के ''खालिस्तानी समर्थक'' रूख के कारण काफी कटू हो गये थे और विशेषकर, हरदीप सिंह निज्झर की हत्या के बाद कटुता काफी बढ़ी थी, क्या, अब रिश्ते सामान्य होंगे।
- यह भी सच है कि चौदह लाख भारतीय मूल के कैनडा वासियों में काफी मतभेद हैं, खालिस्तानियों की गतिविधियों के कारण। यह मतभेद अचानक खत्म नहीं हो जायेंगे, अनिता आनन्द के आने से, पर, रिश्तों में तनाव काफी कम हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करेगा, नई सरकार में अनिता आनन्द को कितना लचीलापन मिलता है, दोनों की सोच व विचारों में कुछ सामंजस्य बिठाने के लिये।

कैनडा की पूर्व लिबरल सरकार के कुछ नेताओं के विपरीत, जिन्हें भारत में खालिस्तानी विचारधारा के प्रति सहानुभूति रखने वाला माना जाता था, आनंद ने अधिक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया है। सन् 2021 से 2023 तक रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने रणनीतिक स्पष्टता और कार्यकुशलता के लिए अपनी पहचान बनाई। उन्होंने कैनडा की नाटो प्रतिबद्धताओं का सफल प्रबंधन किया और राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों में गहरी भागीदारी निभाई, ये सभी बातें उन्हें भारतीय नीति निर्माताओं की नजरों में विश्वसनीय बनाती हैं।

महत्वपूर्ण बात यह है कि आनंद कैनडा में 14 लाख की, भारतीय प्रवासी आबादी के राजनीतिक महत्व को भी समझती हैं। उनका दृष्टिकोण संतुलन पर आधारित रहने की संभावना है: एक ओर कैनडा के कानूनों और स्वतंत्रताओं की रक्षा करना और दूसरी ओर यह सुनिश्चित करना कि इनका उपयोग

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एकल पट्टा प्रकरण में पूर्व आईएएस संधू की ओर से बहस

जयपुर, 14 मई। राजस्थान हाईकोर्ट में बुधवार को एकल पट्टा प्रकरण को लेकर सुनवाई हुई। पूर्व आईएएस जीएस संधू की ओर से मामले में अपना पक्ष रखा गया। वहीं, अदालत ने मामले में गुरुवार को सुनवाई जारी रखना तय किया है। चीफ जस्टिस एमएम

- संधु की ओर से दलील दी गई कि एकल पट्टा निरस्त होने के बाद एसीबी में शिकायत की गई, जबकि कोई अपराध नहीं बनता है।

श्रीवास्तव की एकलपीठ ने ये आदेश पूर्व मंत्री शांति धारीवाल, जीएस संधू, निष्काम दिवाकर और ओंकार मल सैनी की ओर से दायर सात आपराधिक याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान, संधू की ओर से अधिवक्ता एसएस होरा ने पक्ष रखा।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)